

ईरान के 90 प्रतिशत तेल निर्यात का केंद्र, हमले से वैश्विक संकट का खतरा

खार्ग आइलैंड पर कब्जे की योजना: ट्रम्प सरकार के विकल्प

खार्ग आइलैंड से निरंतर तेल भेजा जा रहा है, युद्ध के बावजूद सप्लाई जारी तेल की कीमतों में वृद्धि और ईरान की कमाई प्रभावित होने का अनुमान

तेहरान, एअरि: अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में खार्ग आइलैंड की अहमियत अचानक बढ़ गई है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ट्रम्प सरकार इस आइलैंड पर कब्जे के विकल्प पर विचार कर रही है, क्योंकि यह ईरान की तेल कमाई का सबसे बड़ा केंद्र है। ईरान के लगभग 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी आइलैंड से होता है। यहां बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की सुविधाएं मौजूद हैं। दैनिक आधार पर यहां करीब 70 लाख बैरल तेल जहाजों में भरा जा सकता है। 1960 के दशक में विदेशी निवेश के बाद इस जगह को प्रमुख ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया गया और तब से यह ईरान की तेल सप्लाई की रीढ़ बन गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस आइलैंड पर हमला होने की स्थिति में ईरान बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे वैश्विक संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है।

हमले के संभावित प्रभाव और रणनीति

विशेषज्ञों का मानना है कि खार्ग आइलैंड पर हमला होने पर ईरान की तेल से होने वाली आमदनी अचानक कम हो सकती है और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अनुमान है कि सप्लाई रुकने की स्थिति में तेल की कीमत प्रति बैरल लगभग दस डॉलर तक बढ़ सकती है। ईरान वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 33 लाख बैरल कच्चा तेल और 13 लाख बैरल अन्य तरल ईंधन का उत्पादन करता है। तेल पाइपलाइन सीधे खार्ग आइलैंड तक जाती हैं, जहां इसे स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है और फिर जहाजों में भरकर निर्यात किया जाता है। आइलैंड में लगभग तीन करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है, और वर्तमान में अनुमानित 1.8 करोड़ बैरल तेल मौजूद है। इतिहास में खार्ग आइलैंड रणनीतिक महत्व रखता रहा है। ईरान-इराक युद्ध के दौरान इराकी हमलों में तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसे बाद में पुनः स्थापित किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल अमेरिका और सहयोगी देश ईरान की सैन्य और न्यूक्लियर सुविधाओं को कमजोर करने की रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल खार्ग आइलैंड सीधे युद्ध का मैदान नहीं बना है, लेकिन आने वाले समय में जंग की दिशा तय करने में इसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है।



के तट से 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20 प्रतिशत तेल की वैश्विक आपूर्ति गुजरती है। यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का हमला होता है या जहाजों की आवाजाही रुकती है, तो विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हो सकती है।

युद्ध के बीच तेल निर्यात

जंग के बावजूद खार्ग आइलैंड से तेल निर्यात जारी है। रिपोर्टों के अनुसार 28 फरवरी से अब तक लगभग 1.2 करोड़ बैरल तेल टैंकरों के माध्यम से बाहर भेजा गया है। कई जहाज डार्क फ्लोत के तौर पर काम कर रहे हैं, जहां ट्रैकिंग मशीन बंद रहती है और जहाज की लोकेशन पता नहीं चलती है। खार्ग आइलैंड ईरान पर काम कर रहे हैं, जहां ट्रैकिंग मशीन बंद रहती है और जहाज की लोकेशन पता नहीं चलती है। खार्ग आइलैंड ईरान पर काम कर रहे हैं, जहां ट्रैकिंग मशीन बंद रहती है और जहाज की लोकेशन पता नहीं चलती है।

इसे लागू करने का निर्णय संसद को करना होगा समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी



शरियत कानून में बदलाव पर सावधानी की सलाह

जल्दबाजी से संपत्ति विवादों में कानूनी खालीपन की आशंका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है, लेकिन इसे लागू करने का फैसला अदालत नहीं बल्कि संसद को करना होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जांयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ शरियत कानून 1937 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि शरियत कानून की धाराओं को अचानक रद्द कर दिया



गया तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा, जिससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि अदालत यह घोषित कर सकती है कि मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि इसे मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही हो सकता है, लेकिन कानून बनाना संसद का अधिकार है। शरियत कानून 1937 ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इसके तहत भारत में मुसलमानों के विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत और गुजरिया से जुड़े मामलों में इस्लामी कानून लागू होता है।

बांग्लादेश में विश्वविद्यालय बंद, थाईलैंड में लिफ्ट उपयोग पर रोक

ईरान संघर्ष से एशिया के नौ देशों में तेल संकट



ईंधन बचाने के लिए सख्त कदम, कई स्थानों पर पाबंदियाँ लागू

पाकिस्तान ने मंत्रियों का वेटन और विदेश यात्राएँ रोकें

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण एशिया के कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से कम से कम नौ एशियाई देशों में ईंधन बचाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। कई देशों में सरकारी खर्च

और ऊर्जा उपयोग कम करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। बांग्लादेश में बिजली और ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार ने ई-ड-उल-फितर की छुट्टियाँ भी पहले घोषित कर दी हैं। ईंधन की कमी की आशंका के कारण लोगों में घबराहट बढ़ी और कई स्थानों पर जमाखोरी की स्थिति बनने लगी थी। इसके बाद सरकार ने दैनिक ईंधन विक्री पर सीमा तय कर दी। गैस की कमी का असर

उद्योगों पर भी पड़ा है और कई उर्वरक कारखानों में उत्पादन रोकना पड़ा है। थाईलैंड में ऊर्जा बचत के लिए सरकारी कार्यालयों में लिफ्ट के उपयोग पर रोक लगा दी गई है और कर्मचारियों को सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। कई कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति भी दी गई है। प्रधानमंत्री अनुति चार्नवीराकुल ने ऊर्जा बचत के लिए आवश्यक उपाय लागू करने को कहा है। सरकार ने विदेश यात्राओं को

अस्थायी रूप से रोक दिया है और वातानुकूलन यंत्रों का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का निर्देश दिया गया है। देश के पास फिलहाल लगभग 95 दिन का ऊर्जा भंडार बताया जा रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए सरकार ने मजबूत करना शुरू कर दिया है। साथ ही शोहन इकाइयों को नए ईंधन निर्यात समझौते न करने और कुछ निर्धारित आपूर्ति रोकने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की

चार दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। सांसदों के वेटन में 25 प्रतिशत कटौती तथा सरकारी वाहनों के ईंधन उपयोग में भी कमी की घोषणा की गई है। चीन ने संभावित संकट को देखते हुए कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपने रणनीतिक भंडार मजबूत करना शुरू कर दिया है। साथ ही शोहन इकाइयों को नए ईंधन निर्यात समझौते न करने और कुछ निर्धारित आपूर्ति रोकने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की

पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। वियतनाम ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने की अपील की है, जिससे ईंधन की खपत कम हो सके। दक्षिण कोरिया भी घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य सीमा लगाने की तैयारी कर रहा है। जापान ने राष्ट्रीय तेल भंडार से आवश्यकता पड़ने पर कच्चा तेल जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घरेलू बाजार में कमी न होने दी जाए।

चीन में जातीय एकता के लिए नया कानून प्रस्तावित

विभिन्न समुदायों के बीच विवाह और साझा पहचान को बढ़ावा देने की तैयारी

बीजिंग, एअरि: चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सरकार देश के विभिन्न जातीय समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से एक नए कानून को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित कानून का नाम 'जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने संबंधी कानून' बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार चीन में हान, उइगुर, तिब्बती, मंगोल सहित कुल 56 आधिकारिक जातीय समुदाय हैं। लंबे समय से चीन सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वह अल्पसंख्यक समुदायों पर दबाव डालकर उन्हें बहुसंख्यक

हान संस्कृति में शामिल करने की नीति अपनाती है। प्रस्तावित कानून को चीन की संसद के वार्षिक सत्र में पारित किया जा सकता है। नए कानून के तहत मंदिर भाषा को अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है, जबकि अन्य स्थानीय भाषाओं की भूमिका सीमित हो सकती है। इसके साथ ही अलग-अलग जातीय समुदायों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसी शादियों को रोकने के प्रयासों को गलत माना जाएगा। कानून में यह भी कहा गया है कि माता-पिता अपने बच्चों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति प्रेम और निष्ठा का भाव

सिखाएँ। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति, संगठन या गतिविधि ऐसी बात करती है जिससे विभिन्न समुदायों के बीच नफरत, झगड़ा या अलगाव की मांग बढ़े, तो उस पर रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल है। चीन सरकार का कहना है कि यह कानून देश में एकता मजबूत करने और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कानून को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर दबाव बढ़

सकता है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार यह कानून राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उस नीति को और मजबूत करेगा, जिसके तहत धर्म और संस्कृति को 'चीनीकरण' के अनुरूप ढालने पर जोर दिया जाता है। चीन के कुछ क्षेत्रों में पहले भी जातीय तनाव देखने को मिला है। शिनजियांग क्षेत्र में उइगुर मुस्लिम समुदाय और तिब्बत में स्थानीय बौद्ध समुदाय लंबे समय से सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। वर्ष 2008 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जबकि 2009 में शिनजियांग की राजधानी उरुमची में भी जातीय

झड़पों में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि उइगुर मुसलमानों को बड़ी संख्या में हिरासत शिविरों में रखा गया, हालांकि चीन सरकार इनके पुनर्निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बताती है। विश्लेषकों का मानना है कि प्रस्तावित कानून के माध्यम से शिक्षा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन और संचार माध्यमों सहित कई क्षेत्रों में एक साझा चीनी पहचान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इससे कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका और प्रभाव भी अधिक मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है।

स्कैन करने पर यू ट्यूब का लिंक खुला, बोर्ड बोला तकनीकी त्रुटि

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की गणित परीक्षा के प्रश्नपत्र पर छपे सुरक्षा क्यूआर कोड को स्कैन करने पर एक पुराने अंग्रेजी गीत का यू ट्यूब लिंक खुलने का मामला सामने आया है। नौ मार्च को आयोजित इस परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र की तस्वीरें सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित होने लगीं, जिनमें क्यूआर कोड स्कैन करने पर वर्ष 1987 के गीत 'नेवर गोनो गिव यू अप' का वीडियो खुलने की बात कही गई। मामले के सामने आने के बाद बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह एक तकनीकी त्रुटि है, लेकिन प्रश्नपत्र

बारहवीं के प्रश्न-पत्र पर क्यूआर कोड से खुला गीत

पूरी तरह सुरक्षित और प्रामाणिक है। बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि क्यूआर कोड स्कैन करने पर यू ट्यूब का लिंक खुलने की घटना हुई है, परंतु इससे परीक्षा की सुरक्षा या प्रश्नपत्र की गोपनीयता से कोई समझौता नहीं हुआ है। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि कोड स्कैन करने पर वास्तव में गीत का लिंक खुल रहा था, जबकि कुछ अन्य विद्यार्थियों के अनुसार स्कैन करने पर केवल साधारण अक्षर दिखाई दे रहे थे। इससे भ्रम की स्थिति बन गई और सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित तस्वीरों के कारण प्रश्नपत्र की प्रामाणिकता को लेकर भी चर्चा

शुरू हो गई। बोर्ड के अनुसार प्रश्नपत्रों पर सुरक्षा क्यूआर कोड इसलिए लगाया जाता है ताकि दस्तावेज की पहचान और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। सामान्यतः इसे स्कैन करने पर प्रश्नपत्र का सेट क्रमांक, श्रेणी क्रमांक या सांकेतिक जानकारी प्राप्त होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दस्तावेज असली है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी और आगामी परीक्षाओं में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

राज्यसभा चुनाव से पहले...

तेलंगाना की दो सीटों पर अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को जीत मिली। छत्तीसगढ़ की दो सीटों पर लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताम चुनी गईं, जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर अनुराग शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर चुनाव होना तय है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा। कुल मिलाकर 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। अब शेष 11 सीटों पर मुकाबला होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कोविड...

सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगु और वेणुगोपालन गोविंदन द्वारा 2021 में दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसमें आरोप था कि उनकी बेटीयों की मौत कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण हुई। कोर्ट ने

कहा कि आंकड़े समय-समय पर पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे और मुआवजा नीति का मतलब यह नहीं कि सरकार ने गलती मानी।

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ...

और अपनी बात पूरी नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो कुछ अच्छा होता। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो लगातार सच बोल रहा है और सत्ता इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। उनका इशारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ था, जिन्होंने पिछले 12 वर्षों में सदन में लगातार सच्चाई उजागर की है।

कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस ...

आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया, घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अंतराल 25 दिन कर दी, डिलीवरी एजेंटों के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया और एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार ने घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ा दी है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर अब 913 रुपये में उपलब्ध है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1883 रुपये हो गए हैं। लोगों को इससे काफी परेशानी होगी।

रुपेश खबर असम में ओरुनोदई योजना से आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने का दावा...

40 लाख महिलाओं के खातों में नौ-नौ हजार रुपए भेजे

नईदुनिया ब्यूरो, गुवाहटी: असम सरकार ने ओरुनोदई योजना के अंतर्गत मंगलवार को राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ 9000 रुपये की राशि हस्तांतरित की। यह राशि चार महीनों की सहायता और बोहाग बिहू पर्व के अवसर पर दी गई अतिरिक्त धनराशि को मिलाकर भेजी गई है। यह योजना वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को प्रतिमाह 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस वर्ष जनवरी से चार महीनों की राशि एक साथ देने की घोषणा पहले ही की गई थी। इसके अनुसार लाभार्थियों को मार्च में



कुल 9000 रुपये प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सामाजिक माध्यम एक्स पर संदेश जारी कर कहा कि यह कोई चुनावी उपहार नहीं है, बल्कि

महिलाओं के प्रति सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 3600 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को लगभग 40 लाख महिला प्रधान परिवारों को उनके मूलभूत खर्चों के लिए 1250 रुपये दिए जाते हैं। उनके अनुसार

इस योजना के सकारात्मक परिणाम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और इससे अनेक परिवारों को गरीबी से बाहर आने में सहायता मिली है। सरमा ने यह भी कहा कि इस योजना का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यह एक सीमित और नियंत्रित योजना है, इसलिए इसका लाभ सभी लोगों को नहीं दिया जाता। यदि यह चुनावी योजना होती तो इसका लाभ सभी नागरिकों को मिलता। ओरुनोदई योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिला मुखिया को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देना है, ताकि दवाइयों, दाल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की जरूरतें पूरी हो सकें।